

सं ० ओ०वि०/एफ.डी./१००-८६/३६१६९.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं परमैक पैक हिं (पैपर डिविजन), २७, इण्डरट्रीयल एरिया, फरीदाबाद, के श्रमिक थीं तकी अहमद मार्फत थीं को० एक० शमा, जी० १५, पुराना प्रैस कालोनी, फरीदाबाद तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७, की धारा १० की उपधारा (१) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० ५४१५-३-थम/६८/१५२५४, दिनांक २० जून १९७८, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० ११४९५-जी-थम/५७/११२४५, दिनांक ७ फरवरी, १९५८ द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ७ के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री तकी अहमद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/१२४-८६/३६१७६.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं लाईट कन्ट्रोल, ५६-डी, एन.आई.डी., फरीदाबाद, के श्रमिक थीं रामसुमेर श्रीबास्तव, मार्फत श्री शिवचरन पंडित, गांव सारन, डा० प्रैस कलोनी, फरीदाबाद तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा १० की उपधारा (१) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० ५४१५-३-थम/६८/१५२५४, दिनांक २० जून, १९७८ के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० ११४९५-जी-थम/५७/११२४५, दिनांक ७ फरवरी, १९५८ द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ७ के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री रामसुमेर श्रीबास्तव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक १ अक्टूबर, १९८६

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/१५४-८६/३६४९९.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं अमरपाली स्ट्रॉक्चरल प्रा० लि०, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक ब्रह्मा सिंह, पत्र श्री राजा सिंह, राजेन्द्र कलोनी, लिंक रोड, फरीदाबाद, तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इस में इराके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा १० की उपधारा (१) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० ५४१५-३-थम-६८/१५२५४, दिनांक २० जून, १९७८ के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० ११४९५-जी-थम-५७/११२४५, दिनांक ७ फरवरी, १९५८ द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ७ के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त को उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या ब्रह्मा सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/१६२-८६/३६५०६.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं गिरधर सिंह मिल प्रा० लि०, २७-ए, प्लाट नं० ६४, अमरनगर, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री अनिलव श्री अविल भारतीय किसान मजदूर संगठन, सराय खोजा, फरीदाबाद, तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७, की धारा १० की उपधारा (१) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० ५४१५-३-थम-६८/१५२५४, दिनांक २० जून, १९७८, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० ११४९५-जी-थम-५७/११२४५, दिनांक ७ फरवरी, १९५८, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ७ के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबन्धित मामला है :—

क्या श्री अनिलव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?